P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-2* October- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उदारीकरण के पश्चात उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की स्थितिः कारण एवं सुझाव

Status of Industrial Development in Uttar Pradesh after Liberalization: Reasons and Suggestions

Paper Submission: 15/010/2020, Date of Acceptance: 25/10/2020, Date of Publication: 26/10/2020

जयचन्द यादव
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
रामा महाविद्यालय,
चिनहट, लखनऊ, भारत

सारांश

1991 के बाद सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में बड़े उद्योगों के स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा उद्यमियों को आशय पत्र/इच्छा पत्र जारी किये गये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उदारीकरण के बाद निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों एवं लाइसेन्सीकरण को उदार बनाया गया तथा साथ ही साथ विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की गयी जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदेश के उद्योगों पर दिखाई देता है। उदारीकरण के बाद वर्ष 1992–93 से लेकर वर्ष 2011–12 तक लगभग 20 वर्षों में कुल 1387 बृहद् उद्योगों की स्थापना की गयी, जिसमें कुल 44263.83 करोड़ रू0 का निवेश किया गया एवं 2,21,114 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 112583.59 करोड़ रू0 का औद्योगिक उत्पादन हुआ।

After 1991, as a result of the efforts made by the government, letters of intent / wish letters were issued by the Government of India to entrepreneurs for setting up large industries in the state. After liberalization by the Uttar Pradesh government, liberalization of rules and licensing was liberalized to encourage private enterprises and at the same time provided various facilities whose impact is clearly visible on the industries of the state. After liberalization, a total of 1387 large industries were established in about 20 years from the year 1992-93 to 2011-12, in which a total investment of Rs 44263.83 crore was made and employment was provided to 2,21,114 persons and Rs 112583.59 crore Industrial production was done.

मुख्य शब्द : उदारीकरण, औद्योगिक, विकास, कारण, सुझाव ।
Liberalization, Industrial, Development, Reasons, Suggestion.

प्रस्तावना

औद्योगीकरण अथवा औद्योगिक विकास आधुनिक युग में आर्थिक विकास का पर्यायवाची सा बन गया है। आज विश्व के प्रायः समस्त देश औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि औद्योगीकरण किसी राष्ट्र प्रगति एवं सम्पन्नता का केवल आधार ही नहीं बल्कि उसके आर्थिक विकास का मापदण्ड माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता बहुत अधिक है और स्पष्ट भी। वास्तव में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अभाव में देश के आर्थिक विकास का कार्य अधूरा ही रहेगा। उद्योगों के समुचित विकास के बिना लोगों की आय में अर्थपूर्ण एवं नियमित रूप से वृद्धि लाना सम्भव नहीं है।

औद्योगिक विकास का अर्थ

औद्योगीकरण विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी परम्परागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोधों को समाप्त करके किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को नई दिशा प्रदान करती है। श्री ब्राईस के अनुसार– "विकास के किसी भी सुदृढ़ कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अन्ततः एक व्यापक भूमिका का निर्वहन करना होता है।

यदि कोई देश निर्धनता को दूर करके अपने यहाँ आर्थिक स्थिरता लाना चाहता है, तो इसके लिए औद्योगीकरण को रामबाण औषधि माना जा सकता है, इसीलिए कहा गया है कि "व्यापक रूप में औद्योगीकरण आर्थिक प्रगति एवं ऊँचे जीवन–यापन की कुन्जी है।

अतः औद्योगीकरण आज आधुनिकयुग का एक धर्म बन चुका है जिसका पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य

औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योग किसी भी देश के मजबूत ढाँचे को स्पष्ट करता है। औद्योगिक ढाचे का मजबूत होना प्रदेश या देश के विकास की कसौटी है। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य हैं–

1. उदारीकरण के पश्चात् प्रदेश पर बड़े उद्योगों में होने वाले ढाँचागत परिवर्तनों का अध्ययन।
2. उदारीकरण के दौरान औद्योगिक नीतियों में किये गये संशोधनों का उद्योगों के विकास पर प्रभाव का आकलन करना।
3. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक विकास के माध्यम से कालान्तर में होने वाले बदलाव को समझना।
4. औद्योगिक विकास की भावी प्रगति की सम्भावना की तलाश एवं इसके द्वारा रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्वि करना।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का एक प्रमुख मानक मानते हुए उत्तर प्रदेश में उद्योगों के द्वारा हुए क्षेत्रीय आर्थिक विकास का अनुमान लगाना।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय (2007–2012) में औद्योगिक विकास की स्थिति

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उद्योगों की विशेष भूमिका है। हैं। उदारीकरण के बाद विभिन्न राज्यों में बृहद् उद्योगों के विकास की सम्भावनाएं बढ़ी हैं। उदारीकरण के बाद प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को गतिशीलता प्रदान करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प हो गयी।

1. वर्तमान में निम्न प्रकार के उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं।
2. कृषि आधारित उद्योग– इसमें मुख्यरूप से चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग आते हैं।
3. पशु आधारित उद्योग– चमड़ा उद्योग
4. वन आधारित उद्योग– कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग
5. खनिज आधारित उद्योग– सीमेण्ट उद्योग, बाक्साइड उद्योग, कोयला उद्योग, फास्फोरस उद्योग
6. रसायन आधारित उद्योग– इसमें मुख्यरूप से उर्वरक उद्योग आते हैं।
7. इन्जीनियरिंग उद्योग– डीजल रेल इंजन उद्योग (मडुवाडीह, वाराणसी) वायुयान निर्माण उद्योग, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड आदि।

बृहद् एवं मध्यम् उद्योगों की स्थिति

1991 के बाद सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में बड़े उद्योगों के स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा उद्यमियों को आशय पत्र/इच्छा पत्र जारी किये गये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उदारीकरण के बाद निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों एवं लाइसेन्सीकरण को उदार बनाया गया तथा साथ ही साथ विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की गयी जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदेश के उद्योगों पर दिखाई देता है। इसका विवरण तालिका संख्या– 1 में दिखाई देता है

तालिका संख्या–1

उत्तर प्रदेश में इच्छा पत्र एवं आशय पत्र का विश्लेषण

योजना /वर्ष	प्रार्थना पत्र	जारी इच्छा एवं आशय पत्र	औसतन प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजे गये प्रार्थना पत्र	औसतन प्रतिवर्ष जारी इच्छा एवं आशय पत्र	निवेश (करोड़ रू0)	रोजगार	निरस्त इच्छा एवं आशय पत्र	विचाराधीन इच्छा एवं आशय पत्र
ग्यारहवीं योजना 2007–12	838	172	167	34	7273.86	35909	41	622

स्रोत : उद्योग निदेशालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश

तालिका में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) को देखने से स्पष्ट होता है कि कुल 838 प्रार्थना पत्र भेजे गये जिसमें से भारत सरकार ने 172 इच्छा पत्र एवं आशय पत्र जारी किये जिसमें कुल विनियोग 7273.86 करोड़ रू0 का और 35909 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बृहद् उद्योगों में निवेश एवं रोजगार

प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना थी, क्योंकि इस योजना में प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर (विनिर्माण क्षेत्र में) 12 प्रतिशत थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र विकास का मुख्य कारण यह है कि, प्रदेश लगातार अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि कर रहा है। जैसे ऊर्जा, संचार, सड़क आदि।

तालिका संख्या–4

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में बृहद् एवं मध्यम् आकार के उद्योगों में विकास की स्थिति।

वर्ष	उद्योग	उद्योगों की संख्या	विनियोग (करोड रू0)	रोजगार (संख्या)
2007–08	बृहद् उद्योग	35	2421.59	8,913
	मध्यम् उद्योग	53	391.78	5,019
	कुल उद्योग	88	2813.37	13,932
2008–09	बृहद् उद्योग	10	1210.51	1,672
	मध्यम् उद्योग	35	299.03	1,613
	कुल उद्योग	45	1509.53	3,285

2009–10	बृहद् उद्योग मध्यम् उद्योग	87 83	7006.86 584.95	30,171 7,214
	कुल उद्योग	170	7591.81	37,385
2010–11	बृहद् उद्योग मध्यम् उद्योग	53 72	5054.7 488.43	9,271 6,642
	कुल उद्योग	125	5543.13	15,913
2011–12	बृहद् उद्योग मध्यम् उद्योग	96 50	9422.04 412.49	21,801 5,572
	कुल उद्योग	146	9834.53	27,373
2007–12	कुल बृहद उद्योग कुल मध्यम् उद्योग	281 293	25115.70 2176.68	71,828 26,060
	कुल (बृहद् एवं मध्यम्) उद्योग	574	27292.38	97,888

स्रोत : निवेश प्रकोष्ठ, उद्योग निदेशालय, कानपुर

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 574 बृहद् एवं मध्यम् स्तरीय इकाईयों की स्थापना की गयी, जिसमें कुल 27292.38 करोड़ रू0 का निवेश एवं 97,888 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के दौरान 2004–05 की तुलना में विनियोग में औसतन प्रतिवर्ष वृद्धिदर 193.4 प्रतिशत की हुई थी। वहीं रोजगार में औसतन प्रतिवर्ष वृद्धिदर 63.70 प्रतिशत की हुई।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ाने एवं औद्योगीकरण को तेज करने के लिए अनेकों विश्वस्तरीय सुविधाएं जैसे– सेज, इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एवं एग्रो पार्क के कारण ही ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में औसतन 5.2 प्रतिशत की दर से औद्योगिक विकास हुआ। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर क्या थी? इसका अनुमान तालिका संख्या–5 में औद्योगिक उत्पादन से लगाया जा सकता है।

तालिका संख्या–5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन (करोड़ रू0)	विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन (करोड़ रू0)	बृहद् उद्योगों में उत्पादन (करोड़ रू0)
2007–08	29671.16	17544.47	7736.42
2008–09	29730.5	17579.56	7751.59
2009–10	32317.05	19108.98	8425.97
2010–11	–	–	–
2011–12	–	–	–
3 वर्षों का कुल उत्पादन	91718.71	54233.01	23913.98

स्रोत : इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकलीः रिसर्च फाउण्डेशन, दिल्ली।

उत्तर प्रदेश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के तीन वर्षों के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रथम वर्ष में कुल औद्योगिक उत्पादन 29671.16 करोड़ रू0 का था, हालाँकि 2008–09 में औद्योगिक वृद्धिदर मात्र 0.2 प्रतिशत थी, लेकिन इसके बाद औद्योगिक उत्पादन में सुधार आया और 2009–10 में औद्योगिक उत्पादन 8.7 प्रतिशत वृद्धि के साथ 32317.05 करोड़ रू0 का हो गया। प्रदेश में अगले आने वाले वर्षों में यदि यही औद्योगिक विकासदर कायम रही तो प्रदेश में आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास की वर्तमान स्थिति

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योगों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा उदारीकरण के बाद कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जैसे– लघु उद्योग इकाईयों को क्रय मूल्य में वरीयता, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं त्वरित निर्यात् विकास प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकल मेज व्यवस्था आदि उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में उदारीकरण के बाद लघु उद्योगों में किस प्रकार की प्रगति रही है, इसका विवरण तालिका संख्या –6 में स्पष्ट की गयी है।

तालिका संख्या–6 उदारीकरण के बाद लघु उद्योगों की वर्षवार प्रगति का विवरण

वर्ष	लघु उद्योगों की स्थापना	विनियोग (करोड़ रू0)	रोजगार सृजन (संख्या)	उत्पादन (करोड़ रू0)
2001-2002	29246	270.00	97,155	635.04
2002-2003	30361	272.20	1,12,802	620.32
2003-2004	30454	276.06	1,17,564	383.00
2004-2005	30402	284.34	1,21,102	431.25
2005-2006	30282	262.79	1,25,611	372.71

2006-2007	28487	507.59	1,20,876	944.08
2007-2008	31734	1270.83	1,48,985	4625.21
2008-2009	33302	2046.80	1,71,141	4996.21
2009-2010	34063	3474.12	1,75,504	6751.82
2010-2011	25619	2196.24	1,33,827	3682.89
2011-2012	33532	352.93	1,86,755	-

स्रोत– उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति समीक्षाः– (2009–2010)उद्योग निदेशालय, नियोजन एवं समन्वय अनुभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास में अत्यधिक उतार–चढ़ाव है। 2006–07 में उत्पादन जहाँ 944.08 करोड़ रू0 का था, जो 2009–10 में बढ़कर 6751.82 करोड़ रू0 हो गया, जो अपने आप में एक रिकार्ड था। लघु उद्योगों में इतनी वृद्धि किसी भी वर्ष में नहीं देखी गयी।

सामान्य निष्कर्ष

पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण एक समान नहीं है, कहीं पर औद्योगिकरण अपने चरम पर है तो कहीं पर नाममात्र का है। यदि हम प्रदेश को 5 सम्भागों में बांट कर प्रत्येक सम्भाग में स्थापित बृहद् इकाईयों के प्रतिशत पर ध्यान दें तो यह विषमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

उत्तर प्रदेश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। (1) उत्तर प्रदेश का पर्वतीय सम्भाग (2) पश्चिमी सम्भाग(3) केन्द्रीय सम्भाग (4) बुन्देलखण्ड (5) पूर्वी सम्भाग। इन सम्भागों में कितनी औद्योगिक यूनिटों की स्थापना हुई इनका आकलन तालिका संख्या–8 से लगाया जा सकता है।

तालिका संख्या–8

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां प्रतिशत में

आर्थिक सम्भाग	औद्योगिक इकाईयां प्रतिशत में
पर्वतीय सम्भाग	7.60 प्रतिशत
पश्चिमी सम्भाग	51.30 प्रतिशत
केन्द्रीय सम्भाग	24.20 प्रतिशत
बुन्देलखण्ड	1.50 प्रतिशत
पूर्वी सम्भाग।	15.50 प्रतिशत

स्रोतः Report of the study Group for preparation of a radmap for rapid economic development of U.P. September 2008 (Planning commission state plan division yojana Bhawan Delhi)

उपरोक्त तालिका संख्या–8 को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास सन्तुलित रूप से नहीं हुआ है। पश्चिमी सम्भाग जिसमें पूरे प्रदेश की 51 प्रतिशत औद्योगिक इकाई कार्यरत हैं, तो वहीं पर बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय सम्भाग में मात्र 1.5 प्रतिशत एवं 7.60 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गयी है, जो इस बात का संकेत देती हैं कि प्रदेश में औद्योगिक विषमता अत्यधिक है।

तालिका संख्या–9

क्षेत्रवार औद्योगिक इकाईयों की स्थापना (प्रतिशत में)

क्षेत्र	आगर T	वाराण सी मिर्जापु	गाजियाबा द मेरठ	सुल्तानपु र कानपुर	उत्त र प्रदेश
		र			T
शहरी क्षेत्र	100	93.10	70.10	55.55	80. 50
कस्बा क्षेत्र	–	6.89	9.27	27.27	10. 63
ग्रामी ण क्षेत्र	–	–	20	16.67	8.86

स्रोत : प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ए0के0 सेन गुप्ता, 2008

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75.44 प्रतिशत बृहद् इकाईयां प्राईवेट क्षेत्र में 11.89 प्रतिशत बृहद् इकाईयां संयुक्त क्षेत्र में 12.65 प्रतिशत इकाईयां सहकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। सर्वाधिक हिस्सा निजी क्षेत्र का है। पूरे प्रदेश में इसका हिस्सा 75 प्रतिशत है। है।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में छः मुख्य निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. नये स्थापित वृहद् उद्योग जो मुख्यतः विकसित जिलों में स्थापित हुए इसमें उदारीकरण के बाद वृद्धि देखने को मिली।
2. उदारीकरण के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में वृहद् उद्योगों के निवेश के स्तर में वृद्धि हुई है।
3. प्रदेश के वृहद् उद्योगों में रोजगार के स्तर में कमी देखने को मिली है। जो इस बात का संकेत देता है कि उदारीकरण के बाद निवेश में वृद्धि के साथ रोजगार का स्तर घटा है।
4. रोजगार के स्तर मे कमी वृहद् उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीकी के स्थान पर पूँजी प्रधान तकनीकी के प्रयोग का परिणाम है।
5. प्रदेश में उदारीकरण के बाद वृहद् उद्योग के उत्पादन के स्तर में उतार– चढ़ाव देखने को मिला है।
6. कुल मिलाकर उदारीकरण के बाद औद्योगिक विकास में कमी देखने को मिली है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति के कारण

1. निजी क्षेत्र विकसित जिलों में ही वृहद् उद्योगों की स्थापना में अत्यधिक रूचि दिखाई क्योंकि उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं।
2. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम जनसंख्या घनत्व के कारण वृहद् उद्योगों के लिए भूमि आवंटन में कम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक।
3. भारत का केन्द्र बिन्दु दिल्ली है, जहाँ से विदेशों में वस्तुओं के निर्यात करने की सुविधा उपलब्ध होती, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नजदीक है।

4. विकसित जिलों में विकसित बाजार एंव उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।
5. उदारीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी वृहद् उद्योग स्थापित हुए उनमें अधिकतर उद्योग विकसित जिलों में स्थापित हुए क्योंकि सभी स्थापित उद्योग पूर्व में स्थापित उद्योगों का विस्तार मात्र है।
6. उदारीकरण के बाद वृहद् उद्योगों में निवेश के स्तर के बढ़ने के साथ–साथ रोजगार के स्तर में कमी देखने को मिली है। जो इस बात की ओर संकेत देते हैं, कि सभी वृहद् उद्योग श्रम प्रधान तकनीकी के स्थान पर पूँजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करना प्रारम्भ कर रहें हैं। जिसके कारण कम श्रमिकों का प्रयोग किया जा रहा है।
7. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उदारीकरण के बाद निर्धारित लक्ष्य एंव उपलब्धियों के मध्य अत्यधिक अन्तराल पाया गया है। उदारीकरण के बाद मूल एवं भारी उद्योग स्थापित
8. किये गये, लेकिन कुछ विभिन्न प्रकार के मूल एवं भारी उद्योग ना तो सार्वजनिक क्षेत्र औरना ही निजी क्षेत्र में स्थापित हो सके।
9. उदारीकरण के बाद आयात शुल्क में तेजी से कटौती के कारण प्रदेश के उद्योगों को एकदम से विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा,प्रदेश के उद्योग इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे इसलिए इनकी प्रगति पर विदेशी प्रतिस्पर्धा का बुरा प्रभाव पड़ा,
10. एक तरफ उदारीकरण के बाद वृहद् उद्योगों में निवेश में वृद्धि हो रही थी, तो वहीं बीमार इकाईयां बन्द हो रही थीं जिसके कारण औद्योगिक प्रगति में ठहराव की स्थिति देखने को मिली।
11. इधर 1990 के दशक एवं 2000 के दशक में उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी समस्या बिजली की आयी है। प्रदेश में बिजली की समस्या बहुत व्यापक है।प्रदेश में उद्योगों को 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति न होने के कारण इनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है, जो निश्चित रूप से औद्योगिक गिरावट के मुख्य कारणों में से एक है।
12. प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए पूंजी बाजार का विकसित होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न होने पर निजी क्षेत्र के उद्यमी अपने उद्योगों के विस्तार के लिए साधन एकत्र करने में सफल नहीं हो पाये।
13. 1990 के दशक में उपभोक्ताओं के मांग में काफी संकुचन हुआ है, क्योंकि इस दशक में कृषि क्षेत्र में संवृद्धि–दर कम थी, जिससे रोजगार में गिरावट दर्ज की गयी परिणामस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं की मांगों में कमी आयी, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर पड़ा और औद्योगिक विकास दर में कमी आयी।

सुझाव

1. उत्तर प्रदेश में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाय। अतः राज्य सरकार केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश में आधारभूत वृहद् इकाईयों को स्थापित करने के लिए अनुरोध करें।
2. केन्द्रीय संयुक्त एवं सहकारी सभी क्षेत्रों में भविष्य में जितनी भी इकाईयां स्थापित की जायं, सभी को अधिकान्शतयः औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ें क्षेत्रों एवं सरकार द्वारा घोशित उद्योग शून्य जिलों में स्थापित होना चाहिए।
3. उत्तर प्रदेश की परिस्थिति एवं वातावरण को देखते हुए वृहद् उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक को अपनाया जाय जिससे राज्य में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके।
4. निजी क्षेत्र में वृहद् उद्योगों को स्थापित करने हेतु सरकार सक्रिय भूमिका निभायें। सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक भी रहे तथा राज्य के बाहर के उद्यमियों के द्वारा प्रदेश में वृहद् एवं मध्यम उद्योग लगाने के लिए, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई जैसे बड़े महानगरों में सभाएं भी करे।
5. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक असमानता देखने को मिलती है। अतः राज्य में औद्योगीकरण लाने के लिए क्षेत्रीय असमानता को अतिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।
6. सरकार द्वारा निगमों की संख्या बढ़ायी जाय तथा ऐसे निगमों की स्थापना की जाय जो सुचारू रूप से औद्योगिक इकाईयों का सहयोग एवं सही मार्गदर्शन कर सके।
7. प्रदेश में सरकार को चाहिए कि वृहद् उद्योगों के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था कर 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करे ताकि उद्योगों की उत्पादकता प्रभावित न हो सके और सभी उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उप्रयोग कर सके।
8. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में रोजगार की क्षमता आधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करने पर सरकार को अधिक प्रयास करना चाहिए।
9. सरकार को चाहिए कि सभी बीमार इकाईयों में नयी तकनीकी का इस्तेमाल कर नये सिरे से उनका पुनरूद्धार करे। जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
10. बड़े–बड़े उद्योगपतियों को वृहद् उद्योग लगाने के लिए भूमि के आवंटन में समस्या आ रही है जैसे रिलायन्स प्रदेश में एक बड़ा पावर प्लान्ट लगाना चाहता है। लेकिन प्रदेश में भूमि का आवंटन न होने के कारण यह पावर प्लान्ट अधर में पड़ा है। इसलिए सरकार को भूमि के आवंटन में भी उदार नीति अपनानी चाहिए।

नवीनतम समीक्षा

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उद्योगों का केन्द्रीकरण विकसित जिलों के आस–पास ही हुआ है। जैसे–कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा आदि। अन्य जिलों में उद्योग हैं ही नहीं, यदि हैं भी तो लद्यु एवं कुटीर उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इस उद्योग का भी केन्द्रीकरण पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में औद्योगिक विकास में समानता लाई जाय वस्तुतः ऐसा करना न सम्भव और न व्यवहारिक है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के विकास की अपनी क्षमताएं एवं परिसीमाएं हैं जिनके परे उस क्षेत्र का विकास करना कठिन है। अतः सन्तुलित क्षेत्रीय विकास का तात्पर्य

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में व्याप्त असमानताओं में यथासम्भव कमी लाना है, जिससे कि पिछड़े क्षेत्रों को भी औद्योगिक विकास का लाभ मिल सके इसके सन्दर्भ में राज्य सरकार को सोच–समझकर नीतिया बनानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *कुलश्रेष्ठ, आर0एस0, (2010) औद्योगिक अर्थशास्त्र, आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन*
2. *उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा (2005–06, 2010–11), अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।*
3. *उत्तर प्रदेश (2001, 2009, 2010, 2012), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।*
4. *वार्षिक योजना (2001–02, 2005–06, 2010–11), वाल्यूम–प्रथम और द्वितीय, उत्तर प्रदेश योजना आयोग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार।*
5. *ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) भाग– 1 एवं भाग–2, योजना आयोग भारत सरकार।*
6. *आर्थिक सर्वे रिपोर्ट (2001, 2005, 2010), भारत सरकार।*
7. *योजना आयोग की रिपोर्ट, (2007–08)*
8. *औद्योगिक सर्वे रिपोर्ट (2006–07)*
9. *सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।*
10. *उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति समीक्षा (1990 से 2011), नियोजन एवं समन्वय अनुभाग, उद्योग निदेशालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।*
11. *भारत (2009, 2010, 2011), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली*